

केंद्र सरकार की वित्त-व्यवस्था (अप्रैल-सितंबर 2008)*

इस आलेख में वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान केंद्र सरकार वित्त-व्यवस्था की समीक्षा की गई है। जहां कर संग्रहण में वृद्धि हुई, वहीं घाटे वाले प्रमुख संकेतक यथा राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) अधिक रहे हैं जो आर्थिक सहायता पर अधिक गैर-योजना राजस्व खर्च, ब्याज भुगतान और सामाजिक सेवाओं, अन्य आर्थिक सेवाओं और राज्यों को अनुदान पर योजना राजस्व खर्च, को प्रदर्शित करते हैं।

चालू राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-सितम्बर 2008) की पहली छमाही के दौरान केंद्र सरकार की वित्त-व्यवस्था¹ घाटे के सभी प्रमुख संकेतकों, राशि और जीडीपी के प्रतिशत, दोनों ही रूप में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी को दर्शाती है। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में आरडी और जीएफडी, दोनों अधिक रहे, ये मुख्यतः गैर-योजना और योजना, दोनों के राजस्व खर्च में वृद्धि के कारण हुए। निवल कर राजस्व में अधिक वृद्धि होने के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक हुई। तथापि, गैर-कर राजस्व में वृद्धि की दर कम रही, जो अंशतः ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। पूंजीगत खर्च में वृद्धि की गति बनी रही।

प्रमुख प्रवृत्तियां

क. घाटा संकेतक

राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) नियम, 2004 के अनुसार वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रही और वर्ष 2007-08 के अनंतिम

¹ इस आलेख में समीक्षा लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अप्रैल-सितम्बर 2008 के लेखों के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2007 के तदनुसूची आंकड़ों की तुलना संघ सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेरधारिता के अधिग्रहण में शामिल राशि अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेरधारिता के अधिग्रहण के लिए जून 2007 में भारत सरकार द्वारा किये गये 35,531 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2007 में संघ सरकार को एक बारगी आधिक्य अंतरण के 34,309 करोड़ रुपये को घटाने के बाद की गई है।

* भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के केंद्रीय वित्त-व्यवस्था प्रभाग द्वारा तैयार।

लेखों की तुलना में वर्ष 2008-09 में आरडी के लिए जीडीपी का 0.2 प्रतिशत घटाकर 55,184 करोड़ रुपये (जीडीपी का 1%) का बजट निर्धारित किया गया। वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान आरडी 78,313 करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 141.9 प्रतिशत है जबकि अप्रैल-सितंबर 2007 के दौरान 85.5 प्रतिशत था। यह मुख्यतः ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता, अन्य आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान (विवरण 1) के कारण खर्च पर पड़े दबाव के कारण हुआ है। तथापि वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान प्रतिशत के रूप में बजट अनुमान की तुलना में राजस्व घाटा की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि यह गत दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यह काफी अधिक थी (चार्ट 1)। अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत राजस्व घाटा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक था (सारणी 1)।

वर्ष 2007-08 के अनंतिम लेखों की तुलना में 2008-09 के दौरान जीएफडी, जीडीपी के 0.3 प्रतिशत (एफआरबीएम नियम, 2004 के अंतर्गत निर्धारित जीडीपी के कम से कम 0.3 प्रतिशत कटौती के बराबर) कम होने का बजट 1,33,287 करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) निर्धारित किया

सारणी 1: अप्रैल-सितंबर के दौरान प्रमुख घाटा संकेतक अप्रैल-सितंबर

	जीडीपी से अनुपात के रूप में		बजट अनुमानों से अनुपात के रूप में	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	1.5	1.3	141.9	85.5
सकल राजकोषीय घाटा	1.9	1.7	77.0	53.8
प्राथमिक घाटा	0.3	0.2	-28.8	-104.1

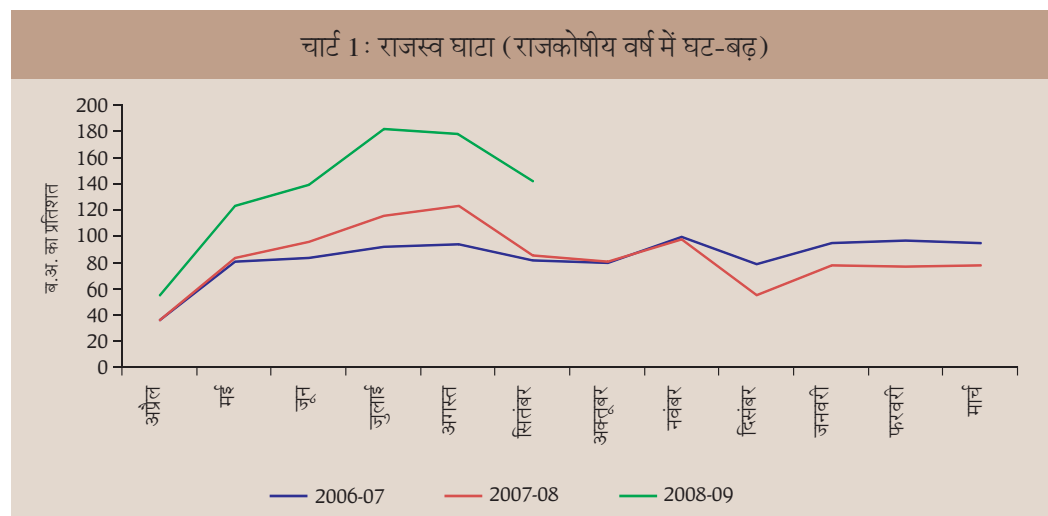
गया था। वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान 1,02,654 करोड़ रुपये का जीएफडी बजट अनुमानों का 77.0 प्रतिशत था, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 53.0 प्रतिशत अधिक था, यह आरडी में बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है (चार्ट 2)। अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.9 प्रतिशत जीएफडी गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरा सकल प्राथमिक घाटा 16,593 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) में 57,520 करोड़ रुपये का आधिक्य परिकल्पित किया गया था (चार्ट 3)।

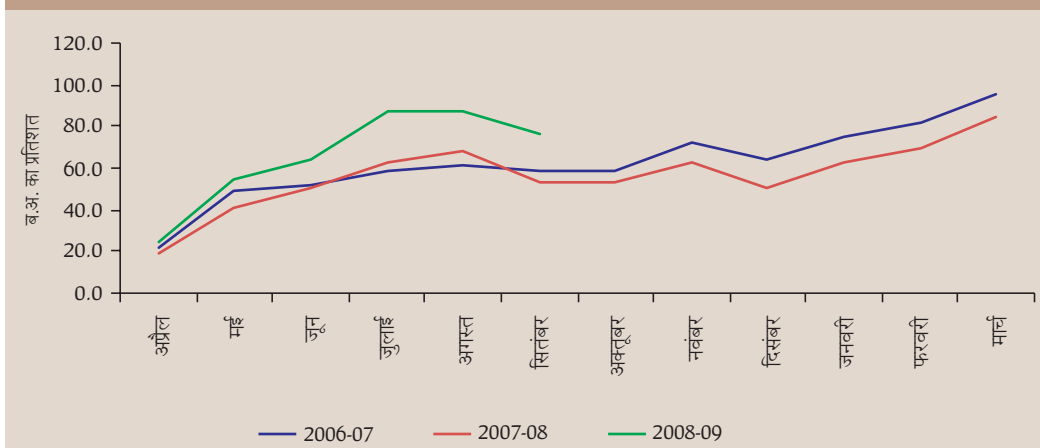
ख. राजस्व स्थिति

अप्रैल-सितंबर 2008-09 के दौरान 2,44,898 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे ने 23.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई जो अप्रैल-सितंबर 2007 के दौरान 22.6

चार्ट 1: राजस्व घाटा (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



चार्ट 2: राजकोषीय घाटा (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



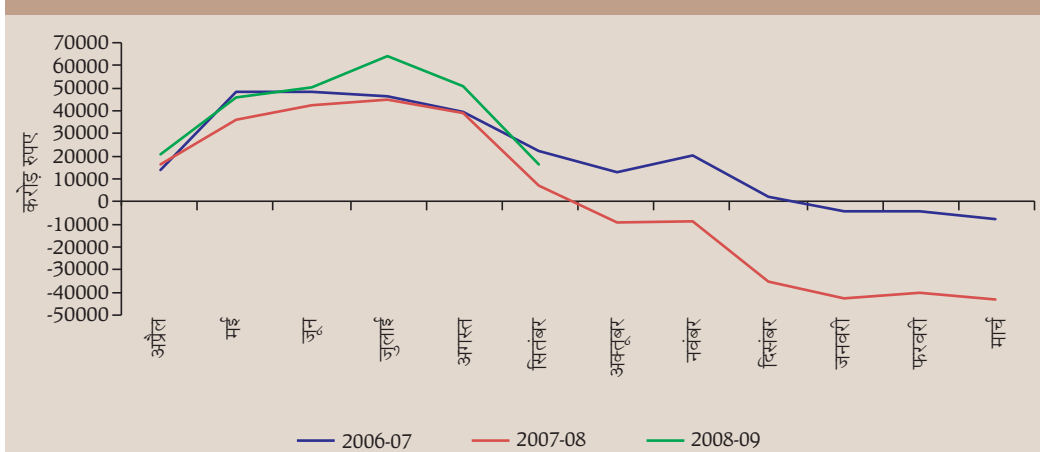
प्रतिशत की तुलना में अधिक है। यह गैर-कर राजस्व की वृद्धि दर में कमी के बावजूद कर राजस्व की वृद्धि दर में बढ़ोतरी (विवरण 1 और चार्ट 4) के कारण हुई है। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रप्तियों का हिस्सा 40.6 प्रतिशत रहा, जो गत वर्ष की पहली छमाही के 40.7 प्रतिशत से थोड़ा कम है।

कर राजस्व

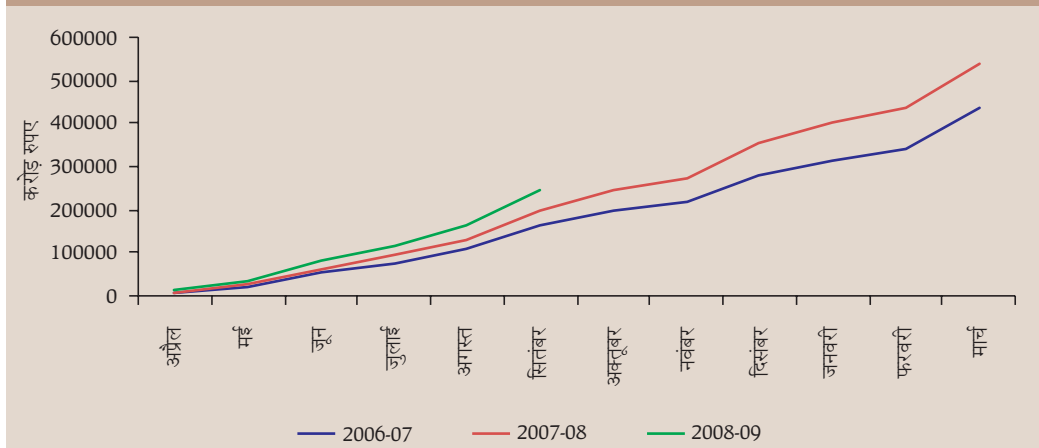
अप्रैल-सितम्बर 2008 के दौरान केंद्र का सकल कर संग्रहण 2,80,141 करोड़ रुपये रहा, जो गत वर्ष की इसी अवधि के 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 25.3

प्रतिशत हो गया। बजट अनुमानों के अनुसार 40.7 प्रतिशत अप्रैल-सितम्बर 2007 के 40.8 प्रतिशत से थोड़ा कम है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को करों के आबंटन में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 27.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) के वित्तपोषण के लिए अधिभार हेतु आबंटन का समायोजन करने के बाद केंद्र के निवल कर राजस्व (2,02,247 करोड़ रुपये) में गत वर्ष की इसी अवधि के 23.5 प्रतिशत

चार्ट 3: प्राथमिक संतुलन (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



चार्ट 4: केंद्र की राजस्व प्राप्तियां (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)

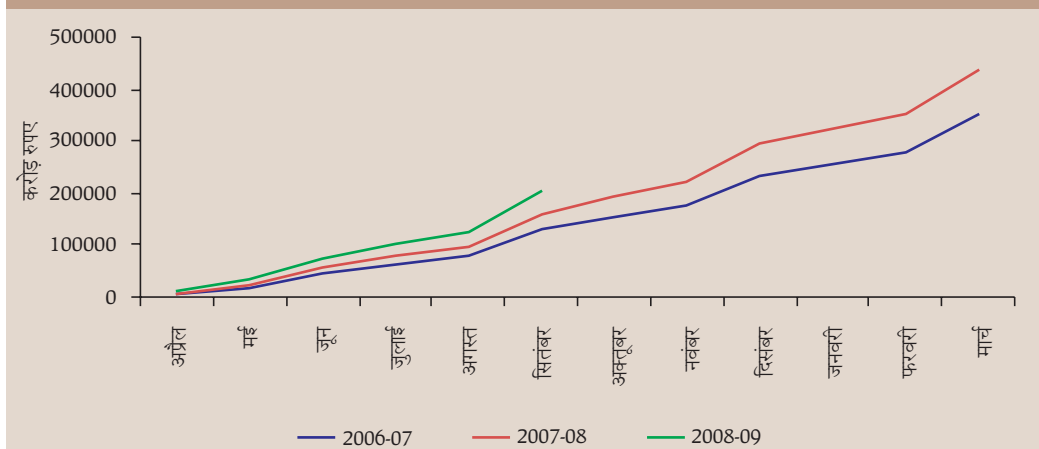


की तुलना में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 5)। यह बजट अनुमान का 39.9 प्रतिशत था जो अप्रैल-सितम्बर 2007(सारणी 2 और विवरण 2) की तुलना में थोड़ा-सा अधिक था।

प्रमुख करों में आयकर की वृद्धि दर 30.7 प्रतिशत रही जो गत वर्ष (38.2 प्रतिशत) की तुलना में कम थी। आयकर के सभी घटकों की वृद्धि दरों में कमी हुई। प्रतिभूति लेनदेन कर (गत वर्ष के 45.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 2.7 प्रतिशत) और

अनुषंगी हित लाभ कर (गत वर्ष के 94.0 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 70.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर में अत्यधिक कमी हुई। 38.2 प्रतिशत की कंपनी कर में वृद्धि की दर भी गत वर्ष (38.6 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी सी कम रही। हालांकि सीमा शुल्क की वृद्धि दर गत वर्ष के 15.9 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 16.9 प्रतिशत हो गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि की दर भी गत वर्ष के 3।4 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 6.6 प्रतिशत हो गई।

चार्ट 5: केंद्र के निवल कर राजस्व (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



सारणी 2: प्रमुख करों के संग्रह की वृद्धि दरें

सारणी 2: प्रमुख करों के संग्रह की वृद्धि दरें					
(प्रतिशत)					
	2007-08 (अप्रैल-सितंबर)	2008-09 (अप्रैल-सितंबर)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (अंतिम लेखे)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4		5
निगम कर	38.6	38.2	29.0	31.3	21.6
आय कर	38.2	30.7	37.8	40.8	16.6
सीमा शुल्क	15.9	16.9	16.7	19.2	18.0
उत्पाद शुल्क	3.4	6.6	8.8	4.8	7.8
सकल कर राजस्व	24.5	25.3	23.6	24.8	17.5
निवल कर राजस्व	23.5	26.0	22.9	24.6	17.5

गैर-कर राजस्व

अप्रैल-सितंबर 2008 में गैर-कर राजस्व 42,651 करोड़ रुपये हुआ जिसमें 13।9 प्रतिशत की कमी हुई, यह कमी मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। लाभांश और लाभ 20,669 करोड़ रुपये के रहे जिनमें 2,607 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। ब्याज प्राप्तियों (7,788 करोड़ रुपये) में 530 करोड़ रुपये की कमी और 'निवल अन्य गैर-कर राजस्व' (वाणिज्यिक विभाग को घटाकर) (13,861 करोड़ रुपये) में 3,141 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

ग) गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

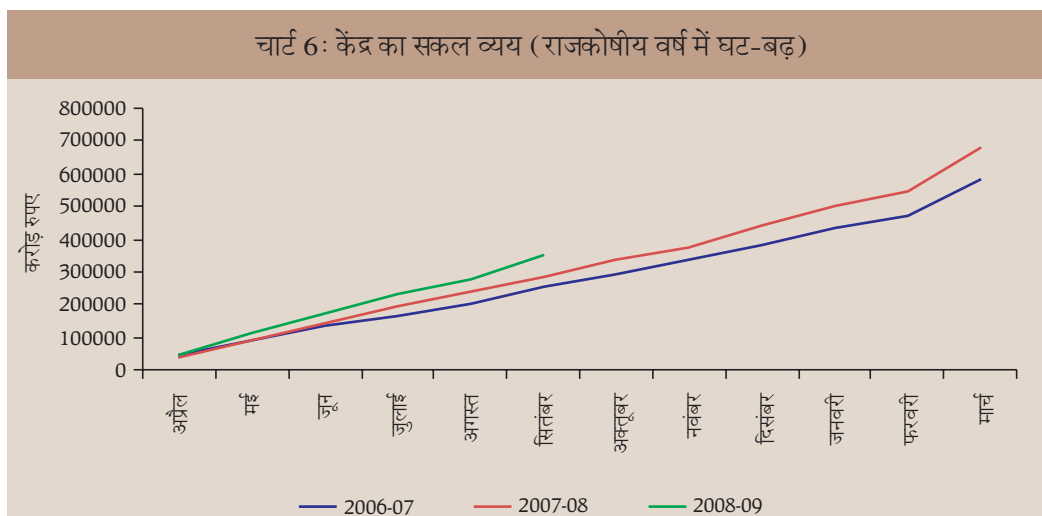
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां, जिनमें ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों के 1,529 करोड़ रुपये शामिल

हैं, एक वर्ष पूर्व की तुलना में कम रहीं। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अप्रैल-सितंबर 2008 में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 10.4 प्रतिशत रहीं, जो गत वर्ष की इसी अवधि के 10.3 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी-सी कम हैं।

घ) खर्च का स्वरूप

अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान कुल पूंजी खर्च 3,49,081 करोड़ रुपये रहा, जिसमें एक वर्ष पूर्व के 12.1 प्रतिशत की तुलना में 23.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट 6)। अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान कुल खर्च बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में 46.5 प्रतिशत रहा जो गत वर्ष की इसी अवधि से अधिक रहा।

चार्ट 6: केंद्र का सकल व्यय (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



योजना खर्च

योजना खर्च 1,08,452 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 25।0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो यह एक वर्ष पहले के 26।0 प्रतिशत की तुलना में कम था (चार्ट 7)। हालांकि, बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में 44।6 प्रतिशत गत वर्ष के 42।3 प्रतिशत की तुलना में अधिक था। योजना खर्च में वृद्धि ग्रामीण विकास, कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति, स्कूली शिक्षा, साक्षरता और बिजली पर खर्च में वृद्धि के कारण हुई (सारणी 3)।

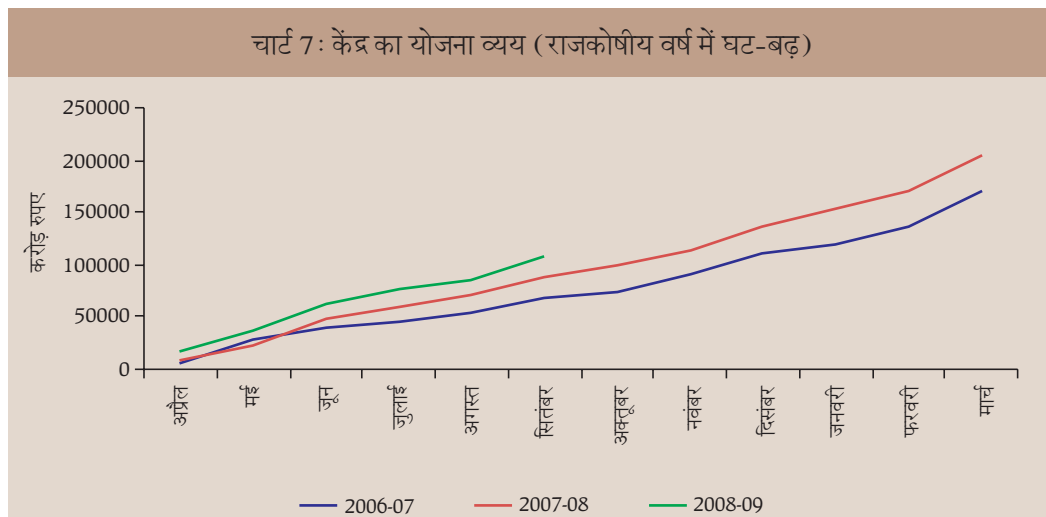
वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान कुल योजना खर्च के भीतर राजस्व घटक 93,727 करोड़ रुपये रहा, जिसमें अधिक वृद्धि हुई जो बजट अनुमान का 44.7 प्रतिशत रहा, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 41.0 प्रतिशत था। योजना राजस्व खर्च में 22,156 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः अन्य आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना अनुदान में वृद्धि के कारण हुई। दूसरी ओर, पूंजीगत घटक 14,725 करोड़ रुपये रहा, जिसमें गत वर्ष की 36.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 3.0 प्रतिशत की कमी हुई (सारणी 4 और विवरण 1)।

गैर-योजना खर्च

अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान 2,40,629 करोड़ रुपये के गैर-योजना खर्च में भी गत वर्ष की इसी अवधि के 6.8 प्रतिशत की तुलना में 23.0 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई (चार्ट 8)। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह 47.4 प्रतिशत रहा, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 41.1 प्रतिशत था। गैर-योजना खर्च में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतानों और प्रमुख आर्थिक सहायताओं के अंतर्गत राजस्व घटक में वृद्धि के कारण हुई (सारणी 4)। रक्षा (राजस्व) खर्च और पेंशन में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि इस अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान में 3.6 प्रतिशत की कमी हुई।

अप्रैल-सितंबर 2008-09 में गैर-योजना राजस्व खर्च में ब्याज भुगतान और प्रमुख आर्थिक सहायताओं का हिस्सा 61.4 प्रतिशत रहा जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 57.5 प्रतिशत रहा था (चार्ट 9)। वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान प्रमुख आर्थिक सहायताओं के खर्च में 19,962 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः उर्वरक आर्थिक सहायता में वृद्धि

चार्ट 7: केंद्र का योजना व्यय (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)



सारणी 3: मंत्रालय/विभाग द्वारा योजना व्यय की प्रमुख मदें

सारणी 3: मंत्रालय/विभाग द्वारा योजना व्यय की प्रमुख मदें				
(करोड़ रुपये)				
मंत्रालय/विभाग	2008-09 ब.अ.	अप्रैल-सितंबर		घट-बढ़
		2008	2007	
1	2	3	4	5
ग्रामीण विकास विभाग	31,500	24,577	15,834	8,743
कृषि और सहकारिता विभाग	10,106	4,516	2606	1,910
पेयजल आपूर्ति विभाग	8,500	4,458	2,899	1,559
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	26,800	8,256	6,875	1,381
ऊर्जा मंत्रालय	6,000	1,675	595	1,080
उच्च शिक्षा विभाग	7,594	2,218	1,347	871
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	15,580	6,156	5,299	857

अर्थात् विनियंत्रित उर्वरक (9,407.2 करोड़ रुपये) और उर्वरक (आयातित) (941.93 करोड़ रुपये) तथा खाद्य आर्थिक सहायता (8,949.4 करोड़ रुपये) के कारण हुई।

पूंजीगत परिव्यय

समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूंजीगत परिव्यय 20,703 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें गत वर्ष के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां रक्षा पूंजीगत परिव्यय में 47.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं गैर-रक्षा पूंजीगत परिव्यय में अप्रैल-

सितम्बर 2007 के इसके स्तर की तुलना में 2.1 प्रतिशत की कमी हुई (सारणी 4)।

ड) सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

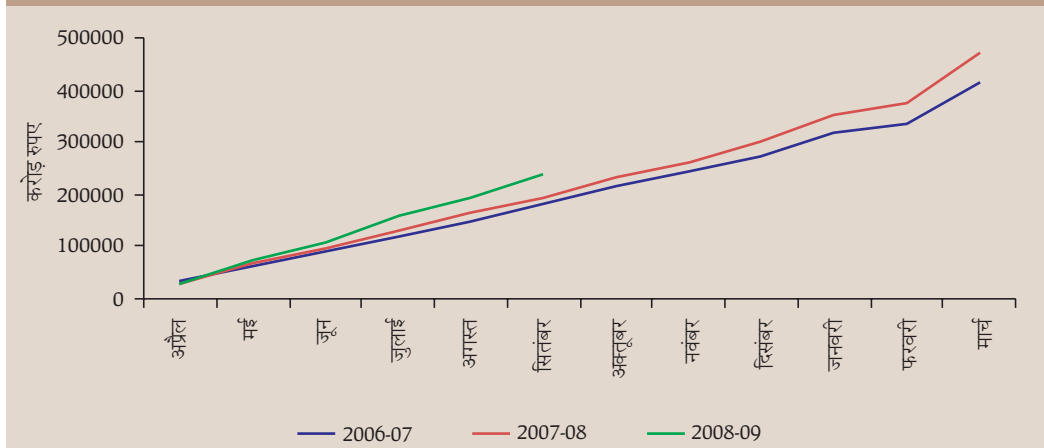
जीएफडी का बाजार उधार और नकदी शेष के आहरण द्वारा वित्तपोषण क्रमशः 62.3 प्रतिशत और 38.5 प्रतिशत रहा। जीएफडी का 28.3 प्रतिशत अल्पकालिक उधार द्वारा वित्तपोषण किया गया। खजाना बिलों (14 दिवसीय) और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों का नकारात्मक अंशदान क्रमशः (-) 26।8 प्रतिशत और (-) 8।6 प्रतिशत रहा (सारणी 5)।

सारणी 4: केंद्र का व्यय

सारणी 4: केंद्र का व्यय				
(करोड़ रुपये)				
मद	अप्रैल-सितंबर		घट-बढ़	
	2008	2007	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. राजस्व व्यय	3,23,211	2,59,080	64,131	24.8
योजनेतर राजस्व व्यय	2,29,484	1,87,509	41,975	22.4
व्याज भुगतान	86,061	72,820	13,241	18.2
प्रमुख सब्सिडियां	54,916	34,954	19,962	57.1
रक्षा राजस्व	27,397	25,817	1,580	6.1
पेंशन	12,247	10,685	1,562	14.6
राज्यो/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	16,074	16,673	-599	-3.6
योजना राजस्व व्यय	93,727	71,571	22,156	31.0
सामाजिक सेवाएं	19,077	13,508	5,569	41.2
राज्यो/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	33,671	29,733	3,938	13.2
अन्य आर्थिक सेवाएं	40,916	28,255	12,661	44.8
आ. पूंजी व्यय	25,870	23,281*	2,589	11.1
ऋण एवं अग्रिम	5,167	5,003	164	3.3
रक्षेतर पूंजी परिव्यय	12,316	12,584*	-268	-2.1
रक्षा पूंजी परिव्यय	8,387	5,694	2,693	47.3
इ. कुल व्यय	3,49,081	2,82,361*	66,720	23.6

*: भारतीय स्टेट बैंक लेन-देनों को घटाकर।

चार्ट 8: केंद्र का योजनेतर व्यय (राजकोषीय वर्ष में घट-बढ़)

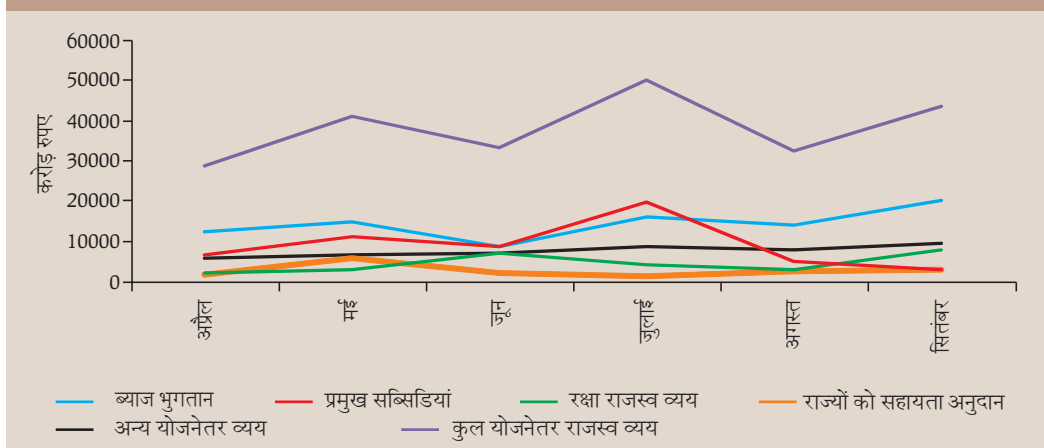


इस वर्ष 1 दिसम्बर 2008 को सकल बाजार उधारराशियां 1,72,904 करोड़ रुपये (बजट अनुमान की 98.4 प्रतिशत) रहीं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1,52,060 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 80.3 प्रतिशत रही थीं। इस वर्ष 1 दिसम्बर 2008 को निवल बाजार उधार राशियां 1,06,816 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 107.9 प्रतिशत) रहीं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 97,766 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 88.3 प्रतिशत) रही थीं।

नकदी प्रबंध

वर्ष 2008-09 (1 दिसम्बर 2008 तक) के दौरान केंद्र सरकार ने 20 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया, जबकि वर्ष 2007-08 की इसी अवधि में 91 दिन के लिए लिया था। वर्ष की शुरुआत 76,686 करोड़ रुपये (मार्च 2008 के अंत में) के नकदी आधिक्य से कर केंद्र सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इन शेषराशियां का उपयोग किया और 4 अगस्त 2008 से 6 अगस्त 2008 के बीच में

चार्ट 9: वर्ष 2008-09 के लिए योजनेतर राजस्व व्यय की मासिक प्रवृत्तियां



सारणी 5: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत : अप्रैल-सितंबर, 2008-09 और 2007-08

1	2008-09		2007-08	
	राशि	हिस्सा (प्रतिशत)	राशि	हिस्सा (प्रतिशत)
2	3	4	5	
1. सकल राजकोषीय घाटा*	1,02,654	100.0	81,200	100.0
2. बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 - दिवसीय खजाना बिल)	63,987	62.3	86,960	107.1
3. अल्पावधि उधार (91 और 182 दिवसीय खजाना बिल)	29,078	28.3	11,583	14.3
4. 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल	-27,550	-26.8	-4,422	-5.4
5. राज्य भविष्य निधियां	120	0.1	191	0.2
6. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (निवल)	7,013	6.8	-13,891	-17.1
7. विशेष जमा राशियां	-481	-0.5	865	1.1
8. अल्प बचतों की बिना पर प्रतिभूतियां	-621	-0.6	-545	-0.7
9. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना	-4	0.0	-254	-0.3
10. बाह्य सहायता	2,315	2.3	2,478	3.1
11. अन्य	-10,702	-10.4	-22,025	-27.1
<i>जिसमें से:</i>				
i. उच्च और विप्रेषण	-1,879	-1.8	-5,551	-6.8
ii. अन्य पूंजी प्राप्ति	-8,823	-8.6	-16,475	-20.3
<i>जिसमें से:</i>				
क) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	-7,581	-7.4	-4,662	-5.7
ख) अग्रिम	-1,992	-1.9	-1,756	-2.2
घ) विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन स्वरूप जारी की गयी विपणनीय प्रतिभूतियां	0	0.0	-5,000	-6.2
ड) राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	0	0.0	-12,101	-14.9
12. अधिशेष नकद का विनिवेश	0	0.0	0.0	0.0
13. उपयोग के कारण नकद शेष राशियों में कमी	39,499	38.5	20,260	25.0
14. अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	0	0.0	0.0	0.0

* : इस सारणी में सकल राजकोषीय घाटे में 35,531 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो कि भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से के अधिग्रहण की लागत है और उसे इस लेन-देन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से किये गये अंतरण की सीमा तक निष्प्रभावी किया गया है।

1 : सकल राजकोषीय घाटे में केंद्र सरकार द्वारा 1,223 करोड़ रुपए के भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से के अधिग्रहण में शामिल लेन-देनों का निवल प्रभाव शामिल है।

अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया। परोक्ष करों के अन्तर्वाह और रिजर्व बैंक से अतिरिक्त निधियों के अंतरण से 7 अगस्त 2008 और 1 सितम्बर 2008 के बीच नकदी आधिक्य हो गया। केंद्र सरकार ने पुनः 2-14 सितंबर 2008 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया ताकि प्राप्तियों और व्यय के बीच असंतुलन को दूर किया जा सके। 30 सितम्बर 2008 को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के पास 41,470 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकदी शेष बनाये रखा। सरकार ने 4-7 नवम्बर 2008 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया तथा 30 नवम्बर 2008 को उसने रिजर्व बैंक में 4812 करोड़ रुपए का अधिशेष बनाये रखा। केंद्र सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का दैनिक उपयोग (30 नवम्बर 2008 तक) 446 करोड़ रुपए था, जबकि पूर्ववर्ती

वर्ष की इसी अवधि में यह 5407 करोड़ रुपए था। केंद्र ने पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में ओवरड्राफ्ट को भी उपलब्ध किया था और दैनिक औसत उपयोग 968 करोड़ रुपए था।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ और बृहद आकलन

वर्तमान राजकोषीय वर्ष (अप्रैल - सितम्बर 2008) के दौरान केंद्र सरकार के वित्त पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निरपेक्ष रूप से और साथ ही सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घाटा बताने वाले सभी महत्वपूर्ण सूचकों में आयी गिरावट का संकेत देते हैं। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा दोनों मुख्यतः योजनागत और गैर-योजनागत दोनों ही श्रेणियों में राजस्व व्यय के बढ़ जाने के कारण

अधिक थे। गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि ब्याज भुगतानों और प्रमुख आर्थिक सहायताओं के कारण हुई। योजनागत व्यय में वृद्धि सामाजिक सेवाओं, अन्य आर्थिक सेवाओं और राज्यों को दिये गये अनुदानों से संबंधित व्यय के कारण थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवल कर राजस्व में हुई ऊँची वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। तथापि, गैर-कर राजस्व में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम थी।

ब्याज प्राप्तियों में आयी गिरावट के कारण ऐसा हुआ। पूंजी व्यय में वृद्धि की गति बनी रही। आने वाले महीनों में एक ओर जहाँ व्यय के बढ़ने की संभावना है, वहीं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षित नरमी के साथ कर राजस्व में कमी आने की संभावना है। परिणामस्वरूप, 2008-09 के शेष हिस्से में घाटे के सूचकों पर दबाव बने रहने की संभावना है।

विवरण 1: केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

मद	वास्तविक (अप्रैल-सितंबर)		बजट अनुमान (वित्तीय वर्ष)		अप्रैल-सितंबर			
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	बजट अनुमानों से प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
					2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजस्व प्राप्तियां	244,898	197,956	602,935	486,422	40.6	40.7	23.7	22.6
2. कर राजस्व (निवल)	202,247	160,500	507,150	403,872	39.9	39.7	26.0	23.5
3. करेतर राजस्व	42,651	37,456	95,785	82,550	44.5	45.4	13.9	19.2
जिसमें से:								
(i) ब्याज प्राप्तियां	7,788	8,318	19,135	19,308	40.7	43.1	-6.4	32.1
4. पूंजी प्राप्तियां	104,183	119,936	147,949	194,099	70.4	61.8	-13.1	32.5
		(85,627) *				(44.1)	(21.7)	-(5.4)
5. ऋणों की वसूली	1,486	2,030	4,497	1,500	33.0	135.3	-26.8	-50.2
6. अन्य प्राप्तियां	43	36,706	10,165	41,651	0.4	88.1	-99.9	-
		(2,397) *				(5.8)	-(98.2)	-
7. उधार	102,654	81,200	133,287	150,948	77.0	53.8	26.4	-6.1
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	349,081	317,892	750,884	680,521	46.5	46.7	9.8	26.2
		(283,583) *				(41.7)	(23.1)	(12.6)
9. योजनेतर व्यय	240,629	231,134	507,498	475,421	47.4	48.6	4.1	26.3
		(195,603) #				(41.1)	(23.0)	(6.8)
10. राजस्व लेखा संबंधी	229,484	187,509	448,352	383,546	51.2	48.9	22.4	8.4
जिसमें से:								
(i) ब्याज अदायगी	86,061	72,820	190,807	158,995	45.1	45.8	18.2	13.8
11. पूंजी लेखा संबंध	11,145	43,625	59,146	91,875	18.8	47.5	-74.5	330.3
		(8,094) #				(8.8)	(37.7)	-(20.2)
12. योजना व्यय	108,452	86,758	243,386	205,100	44.6	42.3	25.0	26.0
13. राजस्व लेखा संबंधी	93,727	71,571	209,767	174,354	44.7	41.0	31.0	23.9
14. पूंजी लेखा संबंधी	14,725	15,187	33,619	30,746	43.8	49.4	-3.0	36.5
15. कुल व्यय (9+12)	349,081	317,892	750,884	680,521	46.5	46.7	9.8	26.2
		(282,361) #				(41.5)	(23.6)	(12.1)
16. राजस्व व्यय (10+13)	323,211	259,080	658,119	557,900	49.1	46.4	24.8	12.3
17. पूंजी व्यय (11+14)	25,870	58,812	92,765	122,621	27.9	48.0	-56.0	176.6
जिसमें से:		(23,281) #				(19.0)	(11.1)	(9.5)
(i) ऋण एवं अग्रिम	5,167	5,003	8,243	7,498	62.7	66.7	3.3	52.1
18. राजस्व घाटा (16-1)	78,313	61,124	55,184	71,478	141.9	85.5	28.1	-11.8
19. राजकोषीय घाटा {15-(1+5+6)}	102,654	81,200	133,287	150,948	77.0	53.8	26.4	-6.1
		(79,978) **				(53.0)	(28.4)	-(7.5)
20. सकल प्राथमिक घाटा {19-10(i)}	16,593	8,380	-57,520	-8,047	-28.8	-104.1	98.0	-62.7
		(7,158) **				-(89.0)	(131.8)	-(68.1)

* : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ अंतरित किये जाने का निवल है जिसका मूल्य भारतीय स्टेट बैंक लेन-देनों कारण 34,309 करोड़ रुपए आंका गया है।

: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक में 35,531 करोड़ रुपए के भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से के अधिग्रहण लागत का निवल है।

स्रोत : नियंत्रक महालेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण 2: अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान केंद्र सरकार की कर वसूली

(करोड़ रुपए)

मद	वास्तविक (अप्रैल-सितंबर)		बजट अनुमान (वित्तीय वर्ष)		अप्रैल-सितंबर			
					बजट अनुमानों से प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. सकल कर राजस्व (1 से 6)	280,141	223,491	687,715	548,122	40.7	40.8	25.3	24.5
1. निगम कर	96,991	70,176	226,361	168,401	42.8	41.7	38.2	38.6
2. आय कर	53,666	41,057	138,314	98,774	38.8	41.6	30.7	38.2
(क) निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	46,349	35,445	120,604	86,829	38.4	40.8	30.8	35.3
(ख) प्रतिभूतियां लेन-देन कर	3,182	3,099	9,000	4,500	35.4	68.9	2.7	45.4
(ग) बैंकिंग नकद लेन-देन कर	323	276	550	645	58.7	42.8	17.0	17.9
(घ) अनुषंगी लाभ कर	3,812	2,237	8,160	6,800	46.7	32.9	70.4	94.0
3. सीमा शुल्क	56,242	48,098	118,930	98,770	47.3	48.7	16.9	15.9
4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	47,870	44,889	137,874	130,220	34.7	34.5	6.6	3.4
5. सेवा कर	24,139	18,343	64,460	50,200	37.4	36.5	31.6	37.2
6. अन्य कर 1,233	928	1,776	1,757	69.4	52.8	32.9	8.4	
आ. एनसीसीएफ वित्तीयन हेतु अधिभार	1,133	1,140	1,800	1,800	62.9	63.3	-0.6	40.9
इ. शेष सकल कर राजस्व	279,008	222,351	685,915	546,322	40.7	40.7	25.5	24.4
ई. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समनुदेशन	76,761	61,851	178,765	142,450	42.9	43.4	24.1	27.0
उ. निवल कर राजस्व	202,247	160,500	507,150	403,872	39.9	39.7	26.0	23.5

एनसीसीएफ : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि

स्रोत : नियंत्रक महालेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार